

# सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर चर्चा

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) इंदौर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार को आइआइटी इंदौर के प्राध्यापक पहले ही प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर स्थापित करने की मांग कर चुके हैं। अब नीति आयोग का ध्यान भी गया है।

संस्थान में नीति आयोग के सदस्य और डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक व रक्षा मंत्री के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डा. विजय कुमार सारस्वत ने बैठक की। इसका उद्देश्य प्रदेश में फैबलेस फाउंड्री के लिए एक केंद्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाना है। फैबलेस मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन शामिल है। बदलते वैश्वक परिदृश्य और मेक इन इंडिया विजन के तहत मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने के आकलन के लिए अधिकारियों ने संस्थान का दौरा किया। यहां सेमीकंडक्टर पर कार्य कर रहे प्राध्यापकों से डा. सारस्वत ने मुलाकात की। इसमें प्रमुख तौर पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (वीएलएसआई) डिजाइन और इसके निर्माण व अनुप्रयोग पर बात की गई। संस्थान के करीब 20

- नीति आयोग के सदस्य डा. विजय कुमार सारस्वत ने बैठक की
- आइआइटी इंदौर के प्राध्यापकों से मुलाकात भी की

## स्वास्थ्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर शोध जारी रखें

डा. सारस्वत ने संस्थान के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए आइआइटी की अनुसंधान क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वलस्टर स्थापित हो सकता है, इस बारे में भी मेंद ली जाएगी। संस्थान के प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आइआइटी को स्वास्थ्य, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीवन रक्षक चिकित्सा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर शोध जारी रखना चाहिए।

प्राध्यापकों ने अब तक हुए कार्य की जानकारी दी। भारत सरकार की पहल के तहत संस्थान में सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर भी चर्चा की गई। डा.

सारस्वत के पहले प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी संस्थान के अधिकारी प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के लिए कई बार बैठक कर चुके हैं।

आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रहे काम : आइआइटी इंदौर में सेमीकंडक्टर पर कार्य कर रहे प्राध्यापक डा. संतोष विश्वकर्मा का कहना है कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर के लिए ईकोसिस्टम बनाने के लिए 76 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह बड़ी राशि है और यह सही समय है, जब मध्य प्रदेश में इसे लेकर कार्य शुरू कर देना चाहिए। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत ताईवान, चीन, साउथ कोरिया, जापान और अन्य देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे लेकर बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। देश में सेमीकंडक्टर तैयार हो सके, इसके लिए सरकार संस्थानों से इसे लेकर काम करने की अपील कर रही है। आइआइटी इंदौर पहले से भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर तैयार करने के लिए आइआइटी इंदौर और प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के बीच भी कई चरणों में बैठक हो चुकी है।